खंड 6 अंक 09 अप्रैल - 2024
केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र
जलांश

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

मार्च केन्द्रीय जल आयोग में उल्लेखनीय प्रगति का महीना रहा है।

केंद्रीय जल आयोग ने इसी महीने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओए ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II और III के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) की स्थापना की शुरुआत की। आईसीईडी, इस एमओए के तहत दस साल के कार्यकाल या डीआरआईपी चरण- II और III की अवधि के लिए काम कर रहा है, जो बांध सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष तकनीकी सहायता, अत्याधुनिक अनुसंधान और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए तैयार है।

परियोजनाओं की समीक्षा जारी रखते हुए, मार्च-2024 के दौरान मेरे द्वारा लद्दाख (यूटी), यूपी, महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश, बिहार, गुजरात और ओडिशा की पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा की गई और इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए। यह जल संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के प्रति हमारे अटूट समर्पण को रेखांकित करता है।

मैंने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की टीम के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने असम और बांग्लादेश में पिछले दो दशकों में परियोजना कार्यान्वयन के अपने अनुभव साझा किए। ये परियोजनाएं एकीकृत बाढ़ जोखिम प्रबंधन, जलवायु लचीलापन और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कटाव नियंत्रण पर केंद्रित हैं। भारत में बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में सीडब्ल्यूसी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में एडीबी टीम को बताया गया और एआई/एमएल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी)आधारित उपकरणों व जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की भविष्यवाणी के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

असम और बांग्लादेश में बाढ़ प्रबंधन योजनाओं (एफएमपी) के संबंध में विश्व बैंक और असम सरकार के अधिकारियों के साथ एक और बैठक हुई। इस बैठक के दौरान, बाढ़ पूर्वानुमान, एफएमपी और नदी रूपात्मक अध्ययन में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका के बारे में बताया गया। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सीडब्ल्यूसी इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी पहलुओं पर सहयोग करने के लिए उत्सुक है।

अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने में हमारी प्रतिबद्धता मजबूत बनी हुई है, जैसा कि पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की दूसरी बैठक में प्रमाणित हुआ है। संवाद को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से, हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों के स्थायी समाधान की दिशा में लगातार प्रगति कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में गंगा पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरों पर एक संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए समिति की चौथी बैठक ने व्यापक योजना और एकीकृत समाधानों के प्रति हमारे समर्पण को प्रदर्शित किया। इस बैठक के दौरान लिए गए निर्णय कटाव से निपटने और कमजोर क्षेत्रों की सुरक्षा में हमारे सक्रिय रुख को रेखांकित करते हैं।

सीडब्ल्यूसी विभिन्न तकनीकी मामलों में राज्यों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। उनके साथ त्रैमासिक संवादों में उनकी ज़रूरतें सामने आ रही हैं और सीडब्ल्यूसी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। हमने आइजोल में पीने के पानी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए मिजोरम में मेड़ के उन्नयन के लिए समाधान प्रदान किया है। हमें केरल राज्य को मुल्लापेरियार बांध के नीचे विभिन्न निर्वहन परिदृश्यों में रूटिंग और बाढ़ अध्ययन भी प्रदान किया गया था। इसलिए, सीडब्ल्यूसी विभिन्न हितधारकों के लिए अधिक प्रासंगिक होने के लिए लगातार काम कर रहा है।

केंद्रीय जल आयोग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसमें सचिव का संबोधन भी शामिल था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनके द्वारा किए जा सकने वाले सामूहिक प्रभाव पर प्रकाश डाला जाए। 07.03.2023 को आयोजित ड्राइंग व पेंटिंग तथा रंगोली प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

केंद्रीय जल आयोग में विश्व जल दिवस उत्साह भरा रहा, जिसमें 125 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने जल संरक्षण के बारे में अपनी समझ का प्रदर्शन करते हुए कविताओं, गीतों और नृत्यों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।

भावी पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन की रक्षा करने की हमारी साझा जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए, जल संरक्षण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

संक्षेप में, मार्च जल प्रबंधन में उत्कृष्टता की हमारी निरंतर खोज और हमारे देश के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों का सामना करने के हमारे अटूट दृढ़ संकल्प का एक प्रमाण रहा है। आइए, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ें वैसे- वैसे, अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता और स्थिरता के प्रति अपना समर्पण जारी रखें।

कुश्विन्द्र

विषयसूची

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

- एशियाई विकास बैंक टीम के साथ बैठक
- भारत-डेनमार्क सहयोग के संबंध में बैठक

परियोजना के संबंध में बैठक

- संकोश परियोजना
- राजस्थान की इंद्रोका एवं बस्तवा माता बांध परियोजना समिति की 22वीं पीआईसी बैठक
- रेणुकाजी बांध परियोजना और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना
- दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश

एनडीएसए और डीआरआईपी

- बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति की चौथी बैठक
- विश्व बैंक विशेषज्ञों द्वारा बांधों के लिए त्वरित जोखिम मूल्यांकन उपकरण विकसित किए गए
- डीआरआईपी चरण- II और एनडीएसए से संबंधित विभिन्न मुद्दे

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

I. बाढ़ और संबंधित मुद्दे

- एफएमपी कार्यों के संबंध में विश्व बैंक और असम सरकार की टीम के अधिकारियों के साथ बातचीत

II. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम

III. अंतर्राज्यीय विवाद

- पेन्नैयार के संबंध में वार्ता समिति की दूसरी बैठक

IV. अन्य गतिविधियाँ

- पश्चिम बंगाल में गंगा पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने हेतु संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने हेतु समिति की चौथी बैठक
- बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए सीडब्ल्यूसी और आईआईएससी, बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा के लिए समिति की तीसरी बैठक
- वाष्पोत्सर्जन (ईटी) सहित सिंचाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए पुनर्गठित कार्य समूह की पहली बैठक
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक
- के.ज.आ. एवं केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन

V. जलाशय निगरानी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

विश्व जल दिवस-2024

स्वच्छता पखवाड़ा-2024

गैलरी

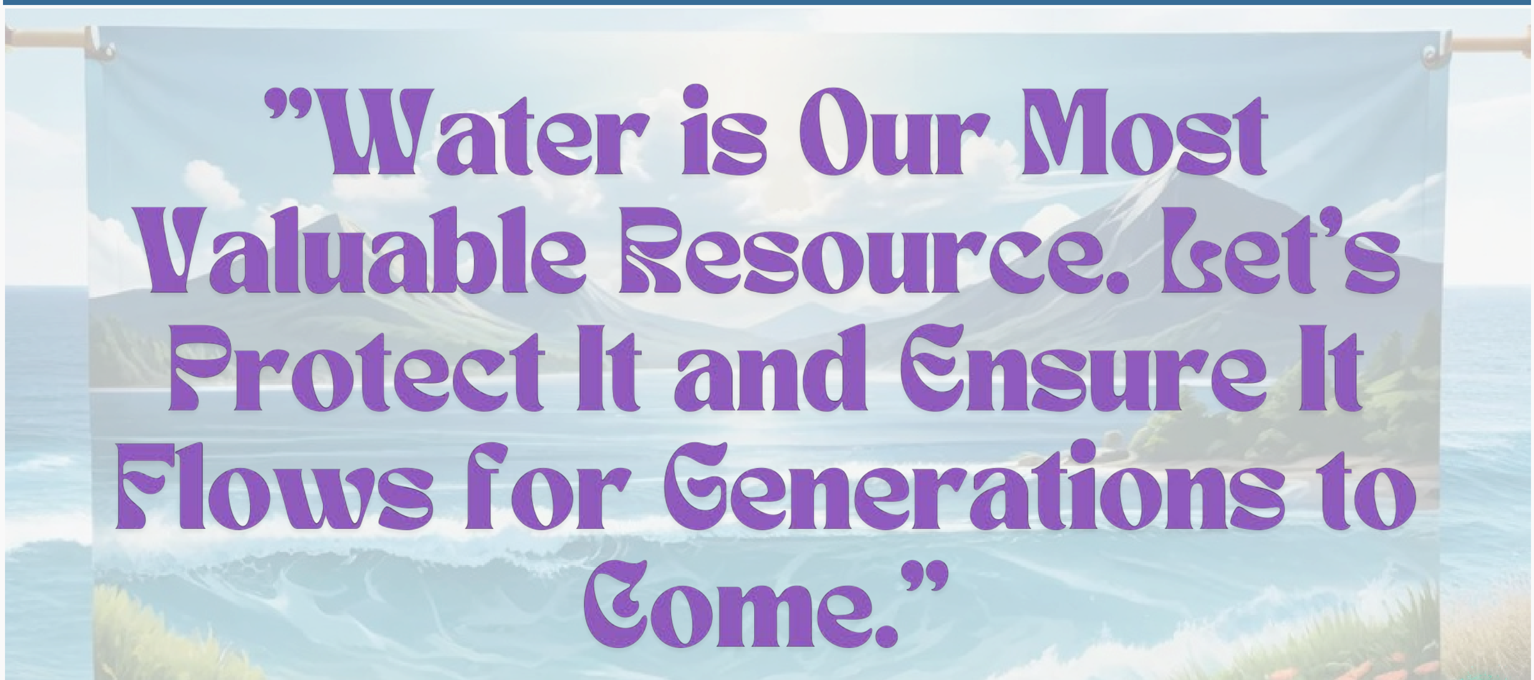

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) टीम के साथ बैठक

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 6 मार्च, 2024 को सुश्री यास्मीन सिद्दीकी, कृषि निदेशक खाद्य, प्रकृति और ग्रामीण विकास (एएफएनआरडी), एडीबी के नेतृत्व में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) टीम के साथ एक बैठक की और इसमें श्री ओलिवियर एल ड्राईयू, वरिष्ठ जल संसाधन विशेषज्ञ, सुश्री एलेक्सिया मिशेल्स, वरिष्ठ जल संसाधन विशेषज्ञ, श्री विकास गोयल, जल संसाधन विशेषज्ञ और श्री हर्ब वीबे, अंतर्राष्ट्रीय जल विशेषज्ञ (एडीबी सलाहकार) शामिल हैं। सीडब्ल्यूसी की ओर से, श्री पी.एम.स्कॉट, सदस्य (आरएम) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

एडीबी टीम ने पिछले 2 दशकों से ब्रह्मपुत्र नदी पर एकीकृत बाढ़ जोखिम प्रबंधन, जलवायु लचीलापन और नदी तट कटाव नियंत्रण से संबंधित असम और बांग्लादेश में एडीबी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं पर एक प्रस्तुति दी।

अध्यक्ष,सीडब्ल्यूसी ने भारत में बाढ़ प्रबंधन संबंधी जो कार्य सीडब्ल्यूसी में प्रगति पर हैं उन विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला, जैसे एकीकृत जलाशय संचालन और गंगा बेसिन में बाढ़ मॉडलिंग; बाढ़ क्षेत्र का मानचित्रण और बाढ़ जोखिम के मानदंड स्थापित करना, नागरिकों के लिए वास्तविक समय में बाढ़ संबंधी जानकारी के लिए फ्लड-वॉच (भारत) लॉन्च करना; एनएचपी, ड्रिप; आदि।

अध्यक्ष ने अग्रिम तैयारियों और अनुकूलन उपायों के लिए जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की भविष्यवाणी करने के लिए मौजूदा प्रणालियों से जुड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित उपकरणों और नवीन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया।

एडीबी की तकनीकी सहायता के प्रस्तावित आउटपुट में शामिल हैं: (i) संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण; (ii) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और मॉडलिंग क्षमताओं के आधुनिकीकरण सहित गैर-संरचनात्मक उपायों का समर्थन करना; (iii) कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं के चयन के लिए राज्य स्तरीय संरचनात्मक स्तर की योजना।

एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया जिसमें असम (भारत) और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में समुदाय-आधारित बाढ़ प्रबंधन और नदी तट कटाव संरक्षण पर एडीबी के अनुभव प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यशाला विस्तृत विचार-विमर्श, सूचनाओं के आदान-प्रदान और भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए उपयोगी होगी।

भारत-डेनमार्क सहयोग के संबंध में बैठक

अक्टूबर, 2021 में डेनिश प्रधान मंत्री की भारत यात्रा से होने वाले भारत-डेनिश सहयोग के तहत परियोजनाओं की समीक्षा के लिए 27.03.2024 को सचिव (डब्ल्यूआर) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, निम्नलिखित परियोजनाओं के सामने आने वाले मुद्दों और आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया:

- स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर)
- स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र।

बैठक में अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, सदस्य (आरएम), सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीई (आईएमओ), सीई (पीडीओ), निदेशक-आईएसएम-2 निदेशालय, निदेशक- आरडीसी-II ने भाग लिया।

Omkareshwar Dam

परियोजना के संबंध में बैठक

संकोश परियोजना

सचिव, DoWR, RD&GR और सचिव, विद्युत ने संयुक्त रूप से संकोश परियोजना के कार्यान्वयन, जल घटक पर विचार आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की, जिसमें सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने 12-03-2024 को श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली में भाग लिया।

राजस्थान की इंद्रोका एवं बस्तवा माता बांध परियोजना समिति की 22वीं पीआईसी बैठक

मुख्य अभियंता, डिज़ाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), राजस्थान में इंद्रोका और बस्तवा माता गांव में बांधों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए परियोजना कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने बस्तवा माता और इंद्रोका बांध परियोजनाओं, जोधपुर राजस्थान के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए सीडब्ल्यूसी मुख्यालय में 28.03.2024 को आयोजित 22वीं बैठक की अध्यक्षता की।

रेणुकाजी बांध परियोजना और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना

रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, एमओजेएस द्वारा 28.03.2024 को एक बैठक ली गई। डिजाइन पहलुओं, लखवार एमपीपी पर वायसाई जलाशय के प्रभाव के मुद्दे और समयसीमा के साथ परियोजनाओं के प्रमुख घटकों की ड्राइंग की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में सदस्य डी एंड आर और डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) इकाई के अधिकारियों ने भाग लिया।

दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश

मुख्य अभियंता, डिज़ाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) ने पारंपरिक कंक्रीट प्रकार के बांध को रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध में बदलने पर चर्चा करने के लिए एनएचपीसी और सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों के साथ 27.03.2024 को दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के वैकल्पिक प्रस्ताव और परिवर्तन ज्ञापन के मूल्यांकन के लिए गठित समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की।

एनडीएसए और डीआरआईपी

बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति की चौथी बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 12.03.2024 को नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुसार गठित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। बैठक में सीडब्ल्यूसी, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एनडीएसए, जीएसआई, एनआरएससी, एनजीआरआई और अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों के अधिकारी, राज्य सरकारों के अधिकारी और बांध सुरक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक के दौरान, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54 (2) के तहत एनडीएसए द्वारा बनाए गए नियमों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान चर्चा किए गए 4 नियमों में से, समिति ने मामूली संशोधनों के साथ तीन नियमों को मंजूरी दे दी।

विश्व बैंक विशेषज्ञों द्वारा बांधों के लिए त्वरित जोखिम मूल्यांकन उपकरण विकसित किए गए

विश्व बैंक विशेषज्ञों द्वारा विकसित बांधों के लिए त्वरित जोखिम मूल्यांकन उपकरणों पर एक बैठक 14.03.2024 को सचिव (डब्ल्यूआर) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, अधिकारियों का एक कोर समूह गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसे देश भर में उपकरण के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। कोर समूह राज्य के लिए प्रशिक्षक और राज्य एजेंसियों के लिए समीक्षक के रूप में कार्य करेगा ताकि उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन की जांच की जा सके।

डीआरआईपी चरण- II और एनडीएसए से संबंधित विभिन्न मुद्दे

डीआरआईपी-II योजना और एनडीएसए से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 27.03.2024 को श्रम शक्ति भवन में सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, धर्म सॉफ्टवेयर के पूर्ण संचालन, जोखिम शमन और पर्यटन क्षमता को शामिल करने की रणनीतियाँ, बांधों के तेजी से जोखिम मूल्यांकन, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सीडब्ल्यूसी, मंत्रालय और एनडीएसए के अधिकारी शामिल हुए।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

I. बाढ़ और संबंधित मुद्दे

एफएमपी कार्यों के संबंध में विश्व बैंक और असम सरकार की टीम के अधिकारियों के साथ बातचीत

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने असम और बांग्लादेश में किए गए बाढ़ प्रबंधन योजना (एफएमपी) कार्यों के संबंध में 22 मार्च 2024 को विश्व बैंक और असम सरकार की टीम के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने बाढ़ पूर्वानुमान, एफएमपी, नदी रूपात्मक अध्ययन आदि की व्यापक प्रणाली सहित सीडब्ल्यूसी के व्यापक कार्यों के बारे में जानकारी दी और उल्लेख किया कि सीडब्ल्यूसी इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी पहलुओं पर सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि असम सरकार विश्व बैंक के साथ-साथ एडीबी की मदद से इन क्षेत्रों में काम कर रही है, इस संबंध में सीडब्ल्यूसी के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करना उपयोगी हो सकता है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम

भारत सरकार के अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और पदेन सचिव की अध्यक्षता में डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा 2016-2017 में शामिल की गई 99 प्राथमिकता वाली चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने इस महीने में कई बैठकें कीं, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन परियोजनाओं को अनुमोदित लागत के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और बाधाओं सहित सभी मुद्दों को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि, इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। विवरण निम्नानुसार हैं:

राज्य का नाम	परियोजनाओं की कुल संख्या	परियोजनाओं का नाम
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख	एक	पार्कचिक सिंचाई परियोजना
उत्तर प्रदेश	दो	i.मध्य गंगा नहर (एमजीसी) परियोजना चरण- II ii. अर्जुन सहायक परियोजना
महाराष्ट्र	छह	i.अरुणा, ii. निचला वर्धा, iii.गोसीखुर्द (एनपी), iv. निचला पेढ़ी, v.कुदाली और मोरना (गुरेघर)
मध्य प्रदेश	चार	i.पेंच परियोजना ii. बरगी डायवर्जन परियोजनाएँ – II iii. बरगी डायवर्जन परियोजनाएँ – III iv. बरगी डायवर्जन परियोजनाएँ - IV
बिहार	दो	i. दुर्गावती जलाशय परियोजना, बिहार ii. पुनपुन बैराज परियोजना, बिहार
गुजरात	एक	सरदार सरोवर परियोजना
ओडिशा	तीन	i. सुवर्णरिखा सिंचाई परियोजना, ii.एकीकृत आनंदपुर बैराज परियोजना, सलपाड़ा और iii.कनुपुर सिंचाई परियोजना

III. अंतर्राज्यीय विवाद

पेन्नैयार के संबंध में वार्ता समिति की दूसरी बैठक

पेन्नैयार नदी पर वार्ता समिति की दूसरी बैठक 27.03.2024 को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी।

बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और इसमें चार सह-बेसिन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में केन्द्रीय जल आयोग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

सह-बेसिन राज्यों के प्रतिनिधियों और समिति के अन्य सदस्यों ने समिति के समक्ष अपने विचार और मामले की स्थिति प्रस्तुत की। पार्टी राज्यों से पहली बैठक में अनुरोध के अनुसार शेष जानकारी/विवरण और दूसरी बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण पर अतिरिक्त विवरण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

IV. अन्य गतिविधियाँ

पश्चिम बंगाल में गंगा पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने हेतु संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने हेतु समिति की चौथी बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने पश्चिम बंगाल में गंगा पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने के लिए एक संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए समिति की चौथी बैठक की।

समिति में सीडब्ल्यूसी, जीएफसीसी पटना, फरक्काबैराज प्रोजेक्ट, सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे, आईडब्ल्यूएआई, एनआरएससी, पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार और डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर के अधिकारी शामिल हैं।

सलाहकार द्वारा विकसित मॉडल की समीक्षा की गई और विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि एकीकृत 1 डी मॉडल में बाढ़ अवधि के लिए गेट संचालन कार्यक्रम पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। बैराज के अपस्ट्रीम और बैराज के डाउनस्ट्रीम के लिए अलग-अलग 2डी मॉडल को अंशांकित(कैलिब्रेट) किया जाएगा।

बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए सीडब्ल्यूसी और आईआईएससी, बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

04.03.2024 को आईआईएससी बैंगलोर में बाहरी समर्थित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II और III के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) की स्थापना के लिए सीडब्ल्यूसी और आईआईएससी, बेंगलुरु के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओए हस्ताक्षर होने की तारीख से दस साल तक या डीआरआईपी चरण- II और III योजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

आईसीईडी भारतीय और विदेशी बांध मालिकों के लिए जांच, मॉडलिंग, अनुसंधान और नवाचार और तकनीकी सहायता सेवाओं में विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। केंद्र मंत्रालय को समर्थन देने

के लिए बांध सुरक्षा पर काम करेगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से बांध सुरक्षा में आने वाली विभिन्न उभरती चुनौतियों का समाधान प्रदान करेगा। यह क्षेत्र-विशिष्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं सहित) भी प्रदान करेगा और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा प्रबंधन में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगा।

आईसीईडी दो मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान करेगा (i) बांधों के लिए उन्नत निर्माण व पुनर्वास सामग्री तथा सामग्री परीक्षण और (ii) बांधों का व्यापक (बहु-खतरा) जोखिम मूल्यांकन। फरवरी 2023 में एमओए पर हस्ताक्षर होने पर आईआईटी रूड़की में पहली आईसीईडी को संस्थागत बनाया गया है।

फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा के लिए समिति की तीसरी बैठक

"फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा" के लिए समिति की तीसरी बैठक 15.03.2024 को दोपहर 3.00 बजे सेवा भवन में आयोजित की गई। समिति ने दूसरी बैठक के निर्णयों की प्रगति और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसमें समिति के टीओआर के अनुसार गंगा/पद्मा के पानी को मोड़कर इचामती नदी के मानसून प्रवाह को बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई।

वाष्पोत्सर्जन (ईटी) सहित सिंचाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए पुनर्गठित कार्य समूह की पहली बैठक

विश्व बैंक के सहयोग से वाष्पोत्सर्जन (ईटी) आधारित जल लेखांकन उपकरण के साथ सिंचाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए पुनर्गठित कार्य समूह की पहली बैठक 28.03.2024 को सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष/भारत सरकार के पदेन सचिव की अध्यक्षता में सेवा भवन, सीडब्ल्यूसी में आयोजित की गई थी।

संशोधित कार्य समूह के संदर्भ की शर्तें हैं:

1) कुछ पायलट अध्ययन परियोजनाओं के साथ विश्व बैंक उपकरण के आधार पर सिंचाई मूल्यांकन उपकरण विकसित करना:

1.1. सिंचाई बेंचमार्किंग के लिए सामान्य प्रणाली

1.2. चयनित सिंचाई प्रणालियों के लिए योजना स्तरीय प्रदर्शन मूल्यांकन (उच्च रिज़ॉल्यूशन पर)

2) सिंचाई मूल्यांकन उपकरणों के आधार पर सिंचाई बेंचमार्किंग संकेतकों को अंतिम रूप देना।

3) एनडब्ल्यूआईसी पोर्टल पर सिंचाई मूल्यांकन उपकरणों के आधार पर सिंचाई बेंचमार्किंग संकेतकों को संचालित करने के लिए रूपरेखा।

4) रिमोट सेंसिंग डेटा के अधिकतम उपयोग पर विचार करते हुए सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल उपयोग दक्षता ढांचा।

पूर्ण सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र और नारायणपुर बायीं तट नहर (एनएलबीसी) परियोजना, कर्नाटक को पायलट परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया है।

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष द्वारा परियोजना अधिकारियों/प्रबंधकों के लिए सिंचाई मूल्यांकन उपकरण पर दिशानिर्देश के विकास और एक एकल संकेतक/सूचकांक के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो परियोजनाओं की बेंचमार्किंग के लिए विभिन्न प्रदर्शन पहलुओं को उपयुक्त भार देकर किसी परियोजना के प्रदर्शन को सारांशित कर सके।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2024 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ. महोदय द्वारा आयोग में पिछली तिमाही में हुई राजभाषाई प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भी ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया। अध्यक्ष,के.ज.आ. महोदय ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंताओं से उनके व उनके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की तथा उन्हें अपेक्षित सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किए। उन्होंनेमुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति एवं नियमों के पालन किए जाने तथा हिन्दी में मूल पत्राचार व नोटिंग अधिकाधिक रूप से हिन्दी में करने हेतु आवश्यक निदेश दिया।

के.ज.आ. एवं केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और भारत सरकार के पदेन सचिव की अध्यक्षता में, केंद्रीयजल आयोग एवं केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 18.03.2024 को के.ज.आ. (मु.) में एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया।

इस संगोष्ठी में अध्यक्ष, के.ज.आ. महोदय के कर-कमलों द्वारा आयोग के हिन्दी अनुभाग द्वारा तैयार की गई अद्यतितआंतरिक शब्दावली एवं केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा तैयार की गई 'स्मारिका' का विमोचन किया गया। के.ज.आ. की शब्दावली में 700 अतिरिक्त शब्दों को जोड़ा गया है। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने के.ज.आ. के सभी अधिकारियों/कर्मचारियोंको आहवान किया कि इस शब्दावली को

कार्यालय में पत्राचार हेतु अधिक से अधिक उपयोग करें। साथ ही इस संगोष्ठी में परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी माननीय अध्यक्ष, के.ज.आ., द्वारा पुरस्कारप्रदान किए गए।

अध्यक्ष महोदय ने के.ज.आ. के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा वे अपने-अपने क्षेत्र व आस-पास के सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने और राजभाषा नीति-नियमों का सुचारु ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु और अधिक उत्साह एवं तन्मयता से अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करें।

V. जलाशय निगरानी

जलाशय निगरानी

सीडब्ल्यूसी साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित संग्रहण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.35% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 28.03.2024 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 64.606 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 36% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 76.991 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 66.644 बीसीएम था। इस प्रकार, 28.03.2024 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय भंडारण का 84% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 97% है।

Map Indicating StateWise Storage Postion
As on 28.03.2024

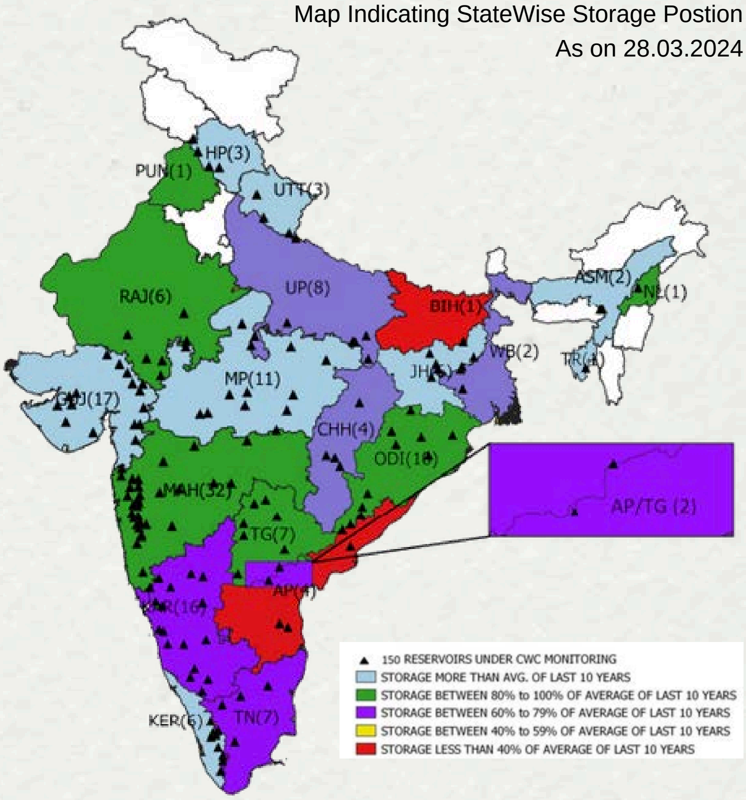

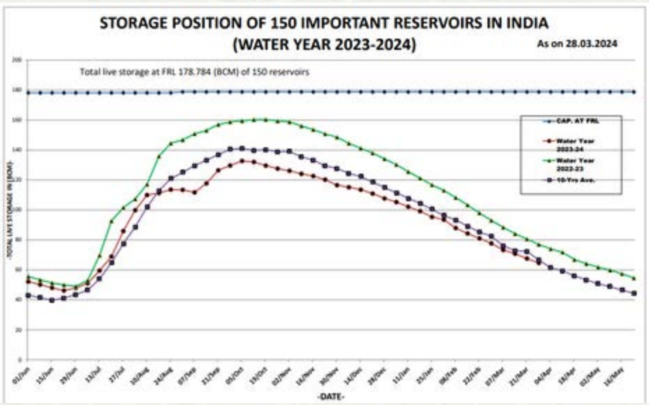

Map Indicating BasinWise Storage Postion
As on 28.03.2024

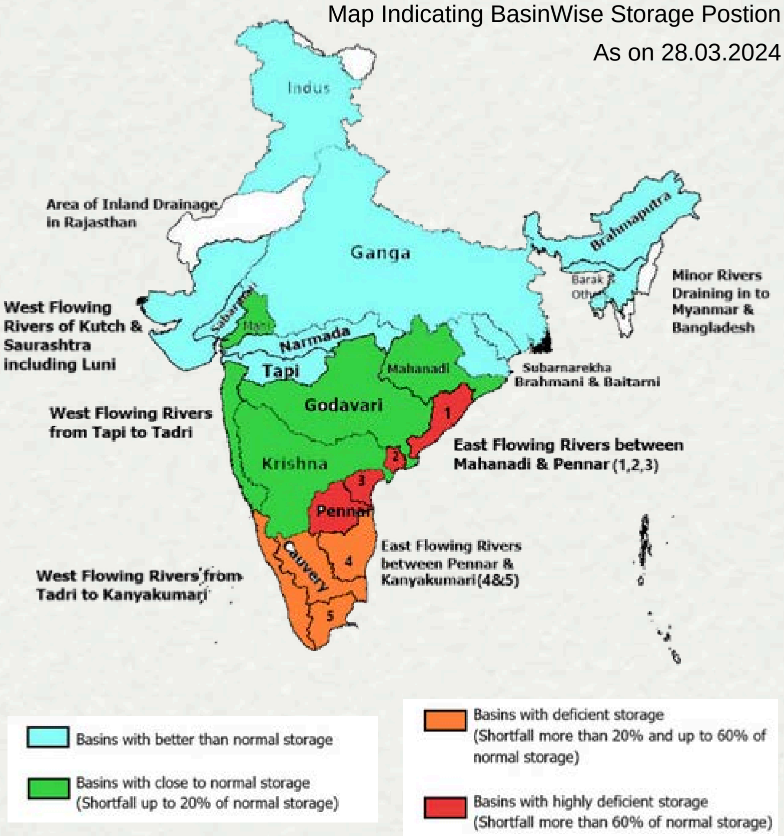

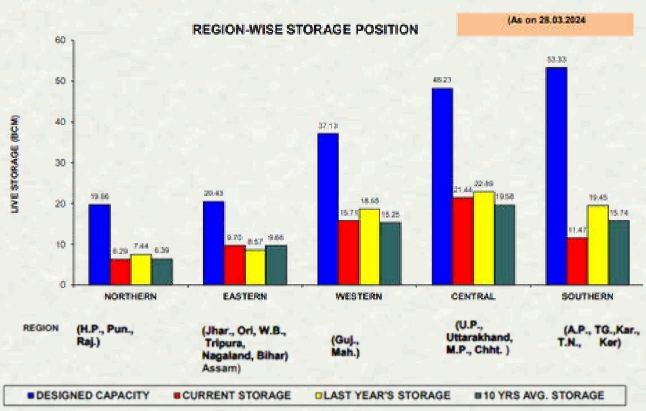

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

सीडब्ल्यूसी (मुख्यालय) द्वारा 7-8 मार्च, 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जिसका विषय था "फोस्टरिंग मेंटरशिप: महिला नेताओं की भावी पीढ़ी को सशक्त बनाना"। 7 मार्च-2024 को रंगोली और ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।

सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली 8 मार्च, 2024 को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। सीडब्ल्यूसी की महिला अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए।

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने अपने संबोधन में इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जिस तरह नारीशक्ति अपने परिवार का पालन-पोषण करती है, उसी तरह वह संगठन में बहुत आवश्यक संतुलन प्रदान करके, नए रास्ते और रचनात्मक तरीकों की खोज करके एक संगठन का भी पोषण करती है। 07.03.2023 को आयोजित ड्राइंग और पेंटिंग और रंगोली बनाने की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि हर दिन महिला दिवस है। महिलाओं को अपने कार्यस्थलों पर खुद को सशक्त बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी आवाज सुनी जाए, भले ही कमरे में केवल एक महिला ही क्यों न हो। महिलाएं न केवल उन्हें सौंपी गई सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करके, बल्कि समय-समय पर उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों को पूरा करके भी कार्यस्थल में एक बड़ा बदलाव लाएंगी।

विश्व जल दिवस

केंद्रीय जल आयोग द्वारा 22 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया! सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने इस बार बच्चों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करने की योजना बनाई। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

यह कार्यक्रम "जल को महत्व देना-इस अनमोल संसाधन के वास्तविक मूल्य को समझना," विषय, पर आधारित था, जिसमें 20 से अधिक बच्चों द्वारा व्यावहारिक भाषण, कविता पाठ और मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों ने जल संरक्षण और स्थिरता के महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चों ने हर बूंद को संजोने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जीवन रेखा की रक्षा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में 125 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को प्रदर्शन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

बच्चों को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने पानी के संरक्षण और इसके सतत उपयोग के महत्व और उन बच्चों की भूमिका पर जोर दिया, जो देश का भविष्य हैं, उन्हें वर्तमान हितधारकों द्वारा की जा रही या नहीं की जा रही कार्रवाई के बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि उनके लिए इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के लिए दबाव डाला जा सके।

स्वच्छता पखवाड़ा-2024

स्वच्छता पखवाड़ा-2024 (16-31 मार्च 2024)

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी द्वारा "स्वच्छता पखवाड़ा-2024" (16 से 31 मार्च,2024) के अंतर्गत 27.03.2024 को केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता जागरूकता शपथ दिलाई गई।

इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जल संरक्षण विषय पर जन जागरूकता हेतु एक नुक्कड़ नाटक (नाटक) भी प्रस्तुत किया गया जिसमें निकट भविष्य में जल संकट के गंभीर परिणामों को दर्शाया गया तथा इससे बचने के लिए अभी से जल संरक्षण करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

माही एवं तापी बेसिन संगठन, गांधीनगर मे स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन

गैलरी

मुख्य अभियंता श्री अनुपम प्रसाद और अधीक्षण अभियंता श्री शिव सुंदर सिंह ने 14 मार्च 2024 को अपने शैक्षिक दौरे पर सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल ऑफ कॉन्शस ट्रांसफॉर्मेशन लखनऊ के कक्षा V के छात्र के साथ बातचीत की। छात्रों को जल संसाधन, जल प्रबंधन, बाढ़ पूर्वानुमान और के.ज.आ. की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई।

विश्व जल दिवस के अवसर पर आज स्कूली बच्चों का दौरा कालिंदी भवन, यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है।

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान एम एंड ईआरओ, के.ज.आ., भुवनेश्वर के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न स्थानों पर स्कूलों के छात्रों द्वारा किए गए स्वच्छता कार्य और वृक्षारोपण अभियान की झलक।

विश्व जल दिवस 2024 के अवसर पर भुवनेश्वर और बुर्ला में आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिताओं की झलक

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री पदमा दोर्जे, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in